

[Shri Pranab Mukherjee]

point increase in the 12-monthly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers with 1960 as the base year. The last D.A. instalment on this basis was sanctioned to the employees with effect from 1.1.1982 when the average index was 440. At the end of March 1982, the average index reached 450.99, thus registering a further eight point increase. Consequently, one more instalment of D.A. to the Central Government employees from 1-4-82 became due for consideration. Government have decided to pay this instalment to the employees. Payment change of this instalment will cost the exchequer Rs. 64.17 crores during the current financial year, the estimated cost of an instalment during a full year being Rs. 70.0 crores. Orders for the payment of this instalment will be issued shortly.

2. Under the existing arrangement, an instalment of Relief to the Central Government pensioners including family pensioners also becomes due for consideration after every increase of 8 points in the average index. The last instalment of Relief was sanctioned on this basis with effect from 1.1.1982, when the average index was 440. Consequent on the average index reaching 450.99 points at the end of March 1982, a further instalment of Relief from 1.4.1982 became due for consideration. Government have also decided to pay this instalment of Relief to the pensioners including family pensioners. This will cost the exchequer Rs. 5.50 crores during the current financial year, the estimated cost of an instalment of relief in a full year being Rs. 6 crores. Orders for the payment of this instalment will be issued soon.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-FIFTH REPORT

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore-South): I beg to move:

"That this House do agree with the Forty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th July, 1982."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Forty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th July, 1982."

The motion was adopted.

NATIONAL HIGHWAYS (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 5)

SHRI K. RAMAMURTHY (Krishnagiri): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Highways Act, 1956.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Highways Act, 1956."

The motion was adopted.

SHRI K. RAMAMURTHY: I introduce the Bill.

FARMERS AND AGRICULTURAL WORKERS BENEFIT FUND BILL*

SHRI K. RAMAMURTHY (Krishnagiri): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a fund for the benefit of the farmers and agricultural workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The questions:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a fund for the benefit of the farmers and agricultural workers."

The motion was adopted.

SHRI K. RAMAMURTHY: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*
(Amendment of Articles 75 and 164)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved.

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मुझे बड़ा दुःख है कि मुझे इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। आम तौर पर जब कोई सदस्य अपना विधेयक रखता है तो उसका विरोध नहीं किया जाता। यह विधेयक दंडवते जी की तरफ से आया है। उनको मैं एक बहुत अच्छा डेमोक्रेट समझता हूँ। जनतंत्रवादो समझते हैं, और जो उनका विधेयक है जिसके द्वारा अनुच्छेद 75, 164 में संशोधन करना चाहते हैं, जनता की जो शक्ति है उसको एक प्रकार की चुनौती है क्योंकि इसके द्वारा वह संविधान में ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं जिससे जनता जिनको धान्त, लक्ष्य और एक व्यक्तित्व होता है। जनता समझती है कि इस सिद्धान्त, लक्ष्य और विचारधारा और पार्टी तथा उसके नेता को वोट दे कर जिन्हें संसद में भेज रहे हैं तो अमुक व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री होगा या अमुक व्यक्ति एक नेता के रूप में चुन कर के भेजा जा रहा है देश की बागडोर सहालने के लिए। इस प्रावधान को कर के जो जनता की इच्छा शक्ति और भावना है उसको कण्ठित करने का प्रयास माननीय दंडवते की तरफ से किया जा रहा है। और इसका हमारे पास उदाहरण भी है। 1980 में जो चुनाव हुआ उससे पहले जो उपचुनाव हुआ उस में देश की

जनता ने इन्दिरा जी को चुन कर के संसद में भेजा। जनता पार्टी ने उनका संसद में निकाला और उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की हर सम्भव चेष्टा की। उसके बावजूद भी देश की जनता ने उनको फिर से चुन कर भेजा . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be brief. If you allow the introduction, you can mention all this during discussion.

श्री हरीश रावत : फिर से उनको चुन कर भेजा, और जनता को मालूम था कि वह प्रधान मंत्री मंत्री होंगी। हमारे विपक्ष के लोगों ने भी अपनी पार्टी के अध्यक्षों को पेश किया जनता के सामने कि अमुक व्यक्ति हमारा प्रधान मंत्री होगा। तो जनता एक विचारधारा और व्यक्तित्व को चुन कर भेजती है। इसलिए जनता जब जानती है कि हम क्या करने जा रहे हैं तब उसकी इच्छा शक्ति पर किसी प्रकार की रोक लगायी जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश के अन्दर पहले से ही राजनीतिज्ञों का एक वर्ग रहा है जो निराशावादी राजनीति से ग्रस्त रहा। जब नेहरू जी यहां थे तो उनके समय में भी इस प्रकार की बात की गई। आज इन्दिरा जी की और नेहरू परिवार की जनप्रियता से कुछ लोग भयभीत हैं। इस प्रकार का बिल उनकी निराशावादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करता है। क्योंकि यह सदन जनता की इच्छा शक्ति से बना हुआ है और इस सदन को इस प्रकार की निराशावादी कठवादी मनोवृत्ति व्यक्त करने का प्लेटफार्म नहीं बनाया जाना चाहिए।

इस आधार पर, माननीय दंडवते जी के प्रति पूरी श्रद्धा प्रकट करते हुए, प्रजातंत्र में जो उनकी आस्था है उसको मानते हुए, उनसे निवेदन करूंगा कि जनता की ताकत को रीस्ट्रिक्ट करने वाला यह विधेयक यहां पेश न करे।

आचार्य भगवान बंबे (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय दंडवते जी ने जो प्रस्ताव